HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2616/2026

Dhanraj S/o Prahlad, R/o Madariya, Police Station Kanwas, District Kota Rural, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. The Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. The Superintendent Of Police, Kota Rural.
4. The Station House Officer, Police Station Kanwas, District Kota Rural.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Surendra Sharma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. M S Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/04/2026

याची–परिवादी की ओर से यह आपराधिक विविध याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची, परिवादी है तथा पुलिस द्वारा इस मामले में निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, अतः उचित निर्देश प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची–परिवादी तथा विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Sakiri Vasu Vs. State of U.P. & Ors. AIR 2008 SC 907 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पक्ष अनुसंधान को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय अनुसंधान को मोनिटर करने व आवश्यक निर्देश देने हेतु सक्षम है तथा ऐसे मामलों में सामान्य रूप से धारा 528 बी.एन.एस.एस./482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है तथा ऐसी

प्रवृत्ति निरूत्साहित होने योग्य है। इस निर्णय के पैरा संख्या 15 व 25 सुसंगत हैं जो निम्नानुसार है–

> "15. Section 156(3) provides for a check by the Magistrate on the police performing its duties under Chapter XII Cr.P.C. In cases where the Magistrate finds that the police has not done its duty of investigating the case at all, or has not done it satisfactorily, he can issue a direction to the police to do the investigation properly, and can monitor the same.
>
> 25. We have elaborated on the above matter because we often find that when someone has a grievance that his FIR has not been registered at the police station and/or a proper investigation is not being done by the police, he rushes to the High Court to file a writ petition or a petition under Section 482 Cr.P.C. We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under Section 154(3) and Section 36 Cr.P.C. before the concerned police officers, and if that is of no avail, by approaching the concerned Magistrate under Section 156(3)."

उपरोक्त विधिक व्यवस्था आदि को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा यह याचिका स्वीकार किया जाना उचित नहीं है, अतः याचिका खारिज की जाती है तथा साथ ही याची–परिवादी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह अपनी व्यथा के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /81